an>

Title: Issue regarding free medicine scheme in the country.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, सरकार के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीबों का है, प्राथमिकता उन्हें दी जानी चाहिए। इसी सोच-विचार के आधार पर यूपीए सरकार ने निशुल्क दवाई योजना की शुरूआत की थी और तत्काली प्रधान मंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोÂाणा की थी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 1300 करोड़ रुपए का आबंटन इस योजना के लिए किया था। आज आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न हुई है कि 30 मई, 2014 को वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब केवल 75 प्रतिशत राशि में केन्द्र सरकार द्वारा केवल 348 दवाएं 23,000 पीएचसी और 5,000 सीएचसी से दी जाएंगी। उसके बाद जुलाई माह में स्वास्थ्य मंत्री जी ने दोबारा यह कहा कि अब केवल 50 दवाओं के लिए ही यह योजना सीमित की जाएगी। उसके दो महीने बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव कहते हैं कि अब इस स्कीम को ड्राप कर दिया है, इंसेंटिवाइजेशन स्कीम अब राज्यों को दे दी है और राज्य सरकारें यह काम करेंगी। अगर यह गरीबों के साथ क्रूर मजाक नहीं है तो क्या है! राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी तो उसने स्पÂट रूप से निशुल्क दवा योजना की शुरूआत की थी। इससे लाखों गरीबों को लाभ मिला था और सिस्टम में सुधार होने के कारण काफी लोग सरकारी अस्पतालों में जाने लगे थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इसमें निजी क्षेत्र का दबाव तो नहीं है कि इस स्कीम को कैंसिल कर दिया गया? जो वादे इन्होंने चुनाव के समय किए थे, क्या वे वादे चुनावी जुमले में ही रह गए? यह सूटबूट की सरकार वापस यह स्कीम लागू करेगी या नहीं, इसका स्पÂटीकरण हम सरकार से चाहते हैं। गरीबों का हक सूटबूट की सरकार देगी या नहीं।

माननीय अध्यक्ष:

श्री राजीव सातव को श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।